निजी चीनी मिलें पेराई की तैयारी शुरू करें

राज्य मुख्यालय | प्रमुख संवाददाता

समाधान की पहल

- प्रमुख सचिव गन्ना ने कहा सरकार चीनी उद्योग की दिक्कतों को लेकर संवेदनशील
- निजी चीनी मिलों के प्रतिनिधियों से अड़ियल रवैया छोड़ने को कहा

आगामी पेराई सत्र के लिए निजी चीनी मिलों के रवैये से पनपे गतिरोध को दूर करने की सरकारी पहल शुरू हो गयी है। 'हिन्दुस्तान' से राज्य के प्रमुख सचिव गन्ना एवं चीनी उद्योग राहुल भटनागर की खास बातचीत में प्रदेश सरकार के इस सकारात्मक रुख का खुलासा हुआ।

श्री भटनागर ने कहा कि प्रदेश सरकार चीनी उद्योग की मौजूदा दिक्कतों को लेकर संवेदनशील है। सरकार ने निजी चीनी मिलों के संकट को देखते हुए पहले 11 रुपए प्रति कुन्तल की दर से प्रवेश शुल्क, गन्ना समितियों के कमीशन आदि विभिन्न देयों की प्रतिपूर्ति की। उसके बाद छह रुपए प्रति कुन्तल की दर से और राहत दी। इसके अलावा केन्द्र सरकार से भी उन्हें ब्याजमुक्त कर्ज मिला। उन्होंने कहा कि निजी चीनी मिलों के प्रतिनिधियों को अड़ियल रवैया छोड़कर सबसे पहले आगामी पेराई सत्र के लिए अपनी मिलों की आवश्यक मरम्मत का काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए ताकि पेराई सत्र समय से शुरू करवाया जा सके। जहां तक रंगराजन कमेटी के लिंकेज फार्मूले का सवाल है तो प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर भी विचार कर रही है। उम्मीद है कि कोई हल जरूर निकल आएगा। श्री भटनागर ने कहा कि निजी चीनी मिलों को किसानों के हित के बारे में भी सोचना चाहिए।

इस बीच, राज्य की निजी चीनी मिलों ने गन्ना मूल्य निर्धारण कमेटी की बैठक में अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव न दिए जाने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन ने तय किया है कि वह रंगराजन कमेटी के लिंकेज फार्मूले को लागू करने की ही मांग करेगी।

Hindustan - 06/10/2014
Pg-02